ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 125-129**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

21वीं सदी में पूर्वोत्तर भारत का सामरिक महत्व एवं चुनौतियाँ

(Strategic importance and challenges of Northeast India in the 21st century)

डॉ0 शैलेन्द्र श्रीवास्तव
सहायक आचार्य–राजनीति विज्ञान विभाग, सी.एम कॉलेज (आर्ट्स एण्ड कॉमर्स) किलाघाट (अंगीभूत इकाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)भारत

Received-26.02.2025, Revised-02.03.2025, Accepted-08.03.2025 **E-mail : dr.ssrivastava660@gmail.com**

***सारांशः** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम प्रान्तों से मिलकर बना पूर्वोत्तर भारत एक ऐसा क्षेत्र है, जो भारत के लिए भौगोलिक एवं सामरिक संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थित यह क्षेत्र चीन, बांग्लादेश, म्यांमार तथा भूटान सहित अनेक देशों के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर भारत का यह क्षेत्र अपनी भू–राजनीतिक स्थिति, संसाधन समृद्धि एवं सुरक्षा चुनौतियों के कारण 21वीं सदी में भी भारत एवं भारतीयों के लिए सामरिक प से अधिक संवेदनशील तथा प्रासंगिक हो गया है। यही कारण है कि यह क्षेत्र वर्तमान में भारत की "एक्ट ईस्ट" (Act East) नीति का केंद्र बिंदु है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना है। इसके बावजूद भी यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और पड़ोसी सीमाओं आदि के कारण आंतरिक एवं बाह्य प से ऐसे चक्रव्यूह से घिरा हुआ है कि इस क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियाँ सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं, जिनका तत्काल व्यापक समाधान अति आवश्यक है।*

अतः इस शीर्षक पर यह शोध पत्र अत्यंत समसामयिक एवं प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल में पूर्वोत्तर भारत के सामरिक महत्व, उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों का समाधान खोजने का यह एक छोटा सा प्रयास एवं माध्यम हो सकता है, ताकि उन नकारात्मक या सकारात्मक चुनौतियों का समाधान/शोध किया जा सके तथा सामाजिक न्याय की बुनियाद पर "सबका साथ–सतत विकास–स्वस्थ पर्यावरण" (Sabka Saath&Satat Vikas&Swasth Paryavaran) आदर्श पूर्वोत्तर भारत की पहचान बन सके।

***कुंजीभूत शब्द–** सामरिक महत्व, भौगोलिक एवं सामरिक संदर्भ, भू–राजनीतिक स्थिति, संसाधन समृद्धि, सुरक्षा चुनौति*

प्रस्तावना– वर्तमान समय में भी पूर्वोत्तर भारत के प्रान्त (अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम) भारत के भू–राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एशिया महाद्वीप के अन्दर दक्षिण एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के संगम पर स्थित, पूर्वोत्तर भारत बांग्लादेश, भूटान, चीन तथा म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है, जो इसे सुरक्षा और आर्थिक संबंधों के कारण दोनों के मध्य एक रणनीतिक अथवा सामरिक प्रवेश द्वार का निर्माण करता है। यही कारण है कि भारत 21वीं सदी में भी पूर्वोत्तर भारत को अधिक महत्व देते हुए अपनी "एक्ट ईस्ट" नीति का पालन करते हुए, आसियान राष्ट्र–राज्यों के साथ–साथ व्यापक हिंद–प्रशांत क्षेत्र के साथ भी मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है। पूर्वोत्तर भारत अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख वैश्विक बाजारों से निकटता, विशेष प से कृषि, पर्यटन, जलविद्युत एवं व्यापार आदि के क्षेत्रों में अपार आर्थिक क्षमता प्रदान करता है।

नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल में भी, पूर्वोत्तर भारत के प्रान्त अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो उनके समग्र विकास में बाधा बन रही हैं। जातीय विविधता और ऐतिहासिक क्षेत्रीय विवादों ने आंतरिक संघर्ष एवं अस्थिरता को जन्म दिया है, जिससे शासन तथा सतत विकास की प्रक्रिया जटिल हो गई है। इस जटिलता ने शैने–शैने अपर्याप्त, खराब तथा जीर्ण–शीर्ण बुनियादी ढांचे (विशेष प से दूरदराज के क्षेत्रों में) को जन्म दिया है, जिसने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सीमित कर दिया है। वनों की कटाई और अनियमित खनन के कारण पर्यावरणीय गिरावट ने इस क्षेत्र के निवासियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यता को बढ़ा दिया है तथा साथ ही यह क्षेत्र भारत के अन्य प्रान्तों की तुलना में अविकसित है, जिससे स्थानीय नागरिकों में हाशिए पर होने की भावना जागृत हो गई है। इस हाशिए एवं अविकसितता के कारण, पड़ोसी राष्ट्र–राज्यों ने पूर्वोत्तर भारत के सामरिक महत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस शोध पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है जो इस प्रकार हैंः

पूर्वोत्तर भारत का भू–राजनीतिक तथा सामरिक महत्व पूर्वोत्तर भारत भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भौगोलिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इस क्षेत्र में सात राज्य (सात बहनें "मअमद "पेजमतें द अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) शामिल हैं तथा इसकी सीमाएँ चीन, बांग्लादेश, म्यांमार तथा भूटान आदि से मिलती हैं। 21वीं सदी में इस क्षेत्र का सामरिक महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह न केवल भारत के लिए एक सुरक्षा चुनौती बन गया है अपितु आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए 'पूर्वोत्तर भारत का भू–राजनीतिक तथा सामरिक महत्व' जो इस शोध पत्र के मुख्य बिंदुओं में से एक है, को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता हैः

क. सीमा की भौगोलिक स्थिति एवं संवेदनशीलताः पूर्वोत्तर भारत को एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति का वरदान प्राप्त है जो भारत तथा दक्षिण–पूर्व एशिया के मध्य प्रवेश द्वार के प में कार्य करता है साथ ही बांग्लादेश, भूटान, चीन एवं म्यांमार के साथ सीमा भी साझा करता है। चीन के साथ इस क्षेत्र की निकटता इसे रणनीतिक प से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, खासकर चल रहे सीमा विवादों के संदर्भ में क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ हिस्सों पर दावा करता है वहीं हिमालय तथा ब्रह्मपुत्र नदी प्राकृतिक बाधाओं के प में कार्य करती हैं जोकि रक्षा बलों के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी पेश करता हैं। चूंकि यह क्षेत्र चीन के साथ सीमा विवाद का केंद्र है, इसलिए चीन तथा पड़ोसी देशों में सक्रिय विद्रोही समूहों से संभावित खतरों के मद्देनजर भारतीय सैनिकों को इस क्षेत्र की सीमाओं पर तैनात किया गया है।

ख. चीन से निकटता अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक स्थितिः भारत के पूर्वी छोर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है तथा यह क्षेत्र दोनों राष्ट्र–राज्यों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के मामले में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jant-Mar. 2025

एक है। अरुणाचल प्रदेश भारत तथा चीन के बीच एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में स्थित है, जो सम्भवतः 1,080 किलोमीटर तक फैला है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस क्षेत्र पर 'सीमा विवाद' ('Border dispute') विवाद का एक प्रमुख कारण है, विशेषकर इसलिए क्योंकि चीन पूरे क्षेत्र को अपने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति तथा हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के साथ अरुणाचल प्रदेश ने 21वीं सदी में रणनीतिक/सामरिक महत्व हासिल कर लिया है। इससे भारत तथा चीन के मध्य लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है, खासकर अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख क्षेत्रों में। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग पूरे क्षेत्र को "दक्षिण तिब्बत" कहता है तथा यह विवाद दोनों राष्ट्र–राज्यों के मध्य तनाव का कारण रहा है। नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल में, चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति एवं बुनियादी ढांचे का विकास इस क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कठिन चुनौतियां पेश कर रहा है।

तिब्बत में चीन द्वारा सड़क, रेलमार्ग तथा हवाई अड्डे आदि के निर्माण ने इस क्षेत्र को ध्यान में ला दिया है क्योंकि इससे चीनी सैन्य गतिशीलता बढ़ गई है, जबकि दूसरी ओर भारत किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए इस क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे एवं रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक या सामरिक स्थिति, चीन से निकटता के कारण पूर्वोत्तर भारत के भू–राजनीतिक तथा सामरिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग. भारत की "एक्ट ईस्ट" (Act East) नीतिः पूर्वोत्तर भारत के भू–राजनीतिक तथा सामरिक महत्व के कारण भारत अपनी "एक्ट ईस्ट" नीति के अन्तर्गत दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य पड़ोसी राष्ट्र– राज्यों के साथ पूर्वोत्तर भारत के संबंधों को और अधिक मजबूत करने की योजना बना रहा है। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा अपितु सामरिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए 'पूर्वोत्तर भारत' भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क स्थापित कर आर्थिक संबंध बढ़ाना है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम तथा कंबोडिया जैसे देशों के साथ इस क्षेत्र की भौगोलिक निकटता ने इसे व्यापार, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और राजनयिक संबंधों आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है, क्योंकि भारत भी हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर भारत के बंगाल की खाड़ी से निकटता, समुद्री व्यापार मार्ग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा हिंद महासागर में भारत की शक्ति प्रदर्शन की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक शक्तियों की उपस्थिति इस क्षेत्र के भू–राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया हैं।

घ. प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक संभावनाः पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी तथा विभिन्न खनिज आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में जलविद्युत की अपार संभावनाएं हैं, ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियाँ ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। असम विशेष प से अपने पेट्रोलियम भंडारों के लिए जाना जाता है, जबकि नागालैंड तथा मिजोरम में कोयले और अन्य खनिजों के भंडार हैं।

प्रकृति ने इस क्षेत्र को समृद्ध जैव विविधता एवं कृषि क्षमता से भी नवाजा है, जिससे यह भारत की खाद्य सुरक्षा तथा निर्यात क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास के माध्यम से 21वीं सदी में पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक क्षमता को खोलना (Unlock) क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, जिससे भविष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है।

पूर्वोत्तर भारत के समक्ष मुख्य सुरक्षा चुनौतियाँ– नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल में भी पूर्वोत्तर भारत अपनी सामरिक स्थिति, जटिल जातीय संरचना और ऐतिहासिक मुद्दों के कारण अनेक बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसलिए इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश इस शोध पत्र के दूसरे मुख्य उपशीर्षक 'पूर्वोत्तर भारत के समक्ष मुख्य सुरक्षा चुनौतियाँ' के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है:

क. आंतरिक विद्रोह एवं जातीय संघर्षः पूर्वोत्तर भारत में जातीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता आदि के कारण अनेक स्थानीय आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन आंदोलनों की मुख्य समस्याएं राज्य के भीतर प्रशासनिक असंतोष, संसाधनों का अनुचित वितरण तथा स्थानीय संस्कृति का संरक्षण आदि से जुड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर असम में विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और नागरिक अशांति भी एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। पूर्वोत्तर भारत के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आंतरिक विद्रोह एवं जातीय संघर्ष है। यह क्षेत्र विभिन्न विद्रोही आंदोलनों का गढ़ रहा है, जो मुख्य प से स्वायत्तता, स्वतंत्रता या स्वदेशी संस्कृतियों की सुरक्षा आदि की मांगों से प्रेरित हैं। पिछले कई दशकों से नागालैंड, मणिपुर, असम तथा त्रिपुरा जैसे प्रान्तों में अनेक सशस्त्र विद्रोही समूह सक्रिय हैं।

पूर्वोत्तर भारत लंबे समय से उग्रवाद एवं आतंकी घटनाओं का सामना कर रहा है। असम, मणिपुर, नागालैंड एवं अन्य प्रान्तों में सक्रिय विद्रोही समूह भारतीय राष्ट्र–राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। ये विद्रोही एवं उग्रवादी प्रायः स्थानीय स्वतंत्रता अथवा अलगाव की मांग करते हैं, जो एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। भारत सरकार ने अनेक उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं परन्तु अनेक समूह अभी भी सक्रिय हैं। 1950 के दशक से नागालैंड में सक्रिय नागा उग्रवाद अनेक शांति समझौतों के बावजूद अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है। इसी प्रकार, असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) United Liberation Front of Assam (ULFA) ने ऐतिहासिक प से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, यद्यपि वर्तमान समय में उग्रवाद को काफी हद तक दबा दिया गया है। वहीं, मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) People's Liberation Army (PLA) जैसे समूहों ने भारतीय राज्य की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की है।

ख. सीमा पार आतंकी एवं उग्रवादः 'पूर्वोत्तर भारत' बांग्लादेश, म्यांमार तथा भूटान के साथ छिद्रपूर्ण सीमा (Porous boundary) साझा करता है, जिससे यह क्षेत्र सीमापार आतंकी एवं विद्रोही (Terrorist and Insurgent) गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। जिसमें म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाएं अत्यंत संवेदनशील हैं क्योंकि इन राष्ट्र–राज्यों से संचालित विभिन्न विद्रोही समूह प्रायः हमले करने के लिए भारत में घुस आते हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, उल्फा (ULFA) एवं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB National Democratic Front of Bodoland) जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह स्थल रहा है इसके अतिरिक्त, इस राष्ट्र–राज्य से सीमा पार अवैध आव्रजन (Illegal immigration) की समस्या भी वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jant-Mar. 2025

ग. मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराधः पूर्वोत्तर भारत को अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी के गलियारे के प में वर्णित किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र गोल्डन ट्राएंगल (Golden Triangle) से सटा हुआ है, जिसे हिंदी में 'स्वर्ण त्रिभुज' कहा जा जाता है अर्थात वह क्षेत्र जहाँ म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस मिलते हैं, जो अपने अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस गोल्डन ट्राएंगल के माध्यम से मादक पदार्थों का प्रवाह, विशेष प से हेरोइन, मेथामफेटामाइन तथा अन्य सिंथेटिक ड्रग्स आदि एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि आतंकी एवं उग्रवादी समूह अधिकांशतः अवैध ड्रग व्यापार के माध्यम से अपने कार्यों को वित्तपोषित करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन प्रयास जटिल हो जाते हैं।

बांग्लादेश से अवैध आव्रजन एक गंभीर समस्या है, जो पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति का कारण भी है, जिसके कारण राजनीतिक दलों ने चुनावों के दौरान इस अवैध आव्रजन को मुख्य मुद्दों में से एक के प में उठाया है। असम तथा अन्य प्रान्त इसे अपने संसाधनों एवं स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं, इसलिए भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है, परन्तु समस्या अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।

घ. पड़ोसी राष्ट्र–राज्य के साथ सीमा विवादः पड़ोसी राष्ट्र–राज्य, विशेषकर चीन तथा बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद पूर्वोत्तर भारत के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है, जहां अरुणाचल प्रदेश भारत–चीन सीमा विवाद का केंद्र है और दोनों राष्ट्र–राज्य एक–दूसरे पर घुसपैठ का आरोप लगाते हैं, जबकि भारत–बांग्लादेश सीमा अवैध प्रवास, भूमि विवाद तथा सीमा पार आतंकी आदि से संबंधित मुद्दों से ग्रस्त है। यद्यपि भारत का भूटान के साथ गहरे सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामरिक संबंध हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भूटान में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, भारत ने भूटान के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है क्योंकि यह क्षेत्र न केवल भारतीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया में भारत की सामरिक स्थिति को भी प्रभावित करता है।

भारत तथा चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख क्षेत्रों पर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, जहां अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ने क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा को जटिल बना दिया है क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को "दक्षिण तिब्बत" के प में दावा करता है और यह विवाद दोनों राष्ट्र–राज्यों के मध्य तनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर, चीन तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में भारी निवेश कर रहा है तथा साथ ही म्यांमार में बढ़ते चीनी प्रभाव के कारण 'पूर्वोत्तर भारत' के लिए सुरक्षा निहितार्थ और भी जटिल होते जा रहे हैं।

ङ. प्राकृतिक आपदाएँ एवं पर्यावरण सुरक्षाः पूर्वोत्तर भारत अपने पहाड़ी इलाकों तथा भूकंपीय गतिविधियों के कारण भूगर्भीय प से संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ बाढ़, भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर आती रहती हैं, विशेष प से ब्रह्मपुत्र नदी जो अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है, जिससे हज़ारों लोग विस्थापित होते हैं तथा उनकी आजीविका बाधित होती है। इससे न केवल सामान्य जीवन प्रभावित होता है अपितु सैन्य गतिविधियों एवं आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए भी चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

रणनीतिक अथवा सामरिक प्रतिक्रियाएँ तथा नीतिगत सिफारिशें आठ राज्यों वाला पूर्वोत्तर भारत रणनीतिक अथवा सामरिक प से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएँ चीन, बांग्लादेश, म्यांमार तथा भूटान जैसे अनेक राष्ट्र–राज्यों से मिलती हैं। यह क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं कूटनीतिक जुड़ाव का केंद्र बिंदु रहा है। इसलिए, भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और पूर्वोत्तर भारत के विकास को सुनिश्चित करके अपनी रणनीतिक क्षमता का विकास करना होगा जिसके लिए सुरक्षा, विकास एवं कूटनीति आदि को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अतः इस शोध पत्र के तृतीय प्रमुख उपशीर्षक अर्थात 'रणनीतिक अथवा सामरिक प्रतिक्रियाएँ तथा नीतिगत सिफ़ारिशें' में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत उपरोक्त उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तरों का अन्वेषण करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है।

क. उन्नत बुनियादी ढांचे का विकासः पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक अथवा सामरिक चुनौतियों का सामना करने की दिशा में प्रथम चरण बेहतर सड़कें, रेलवे, वायुमार्ग तथा संचार नेटवर्क सहित उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास है, जो सतत विकास के अंतर्गत सुरक्षा एवं आर्थिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने पहले ही अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रारम्भ कर दी हैं, जिनमें "सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम" (बीएडीपी) (BADP ÞBorder Area Development Programmeß) शामिल है, जिसमें सीमा सड़कों तथा संपर्क परियोजनाओं आदि का निर्माण शामिल है।

ख. सुरक्षा एवं आतंक विरोधी अभियानः भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल तथा असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सीमा सुरक्षा एवं आतंक विरोधी अभियान चलाते हैं तथा साथ ही वहां उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते हैं। यद्यपि "आंतरिक उग्रवाद से निपटने के लिए सैन्य, खुफिया तथा विकासात्मक दृष्टिकोणों को मिलाकर एक समन्वित 'आतंक–रोधी रणनीति' ('Counter&terror strategy') की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बल सुरक्षा बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाएं, साथ ही एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जिसमें संवाद, विकास एवं स्थानीय शिकायतों का निवारण भी शामिल होना चाहिए"।

पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राष्ट्र–राज्य के साथ रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत ने भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार जैसे राष्ट्र– राज्य के साथ द्विपक्षीय समझौतों को मजबूती से बढ़ावा दिया है। पड़ोसी राष्ट्र–राज्य, विशेष कर म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ 'आतंक–रोधी' (Anti&terrorism) अभियानों में अधिक सहयोग की भी आवश्यकता है, जिससे सीमा पार खुफिया जानकारी साझा की जा सके और सीमा पार सक्रिय विद्रोही समूहों से निपटने के लिए संयुक्त अभियानों को और मज़बूत तथा सशक्त किया जा सके।

ग. **पड़ोसी राष्ट्र–राज्य के साथ कूटनीतिक संबंध** पूर्वोत्तर भारत के लिए कूटनीतिक प से, भारत को सीमा विवादों को सुलझाने एवं सीमा पार आतंकीयों से निपटने के लिए अपने पड़ोसी राष्ट्र–राज्य के साथ अधिक मजबूती से जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत ने अपनी "एक्ट ईस्ट" नीति के अन्तर्गत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया तथा अन्य पड़ोसी राष्ट्र–राज्य से जोड़ने की योजना बनाई है। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास तथा व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा अपितु सामरिक प से भी भारत की स्थिति मजबूत होगी।

जहां तक पड़ोसी राष्ट्र–राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों का प्रश्न है, भारत को भविष्य में पड़ोसी राष्ट्र–राज्यों के साथ राजनयिक संबंध इस तरह से बनाने चाहिए जो पूर्वोत्तर भारत तथा भारत के हित में हों, जैसे कि भारत सरकार द्वारा अधिक सीमा

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jant-Mar. 2025

व्यापार चौकियां स्थापित करना, संयुक्त सीमा प्रबंधन के लिए पहल करना, शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से भारत–बांग्लादेश सीमा विवाद का समाधान करना और म्यांमार के साथ मिलकर काम करना आदि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पार गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने वाले विद्रोही समूहों पर अंकुश लग सके और उन्हें उखाड़ फेंका जा सके, जोकि पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता के लिए एक आवश्यक कदम हो सकता है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत के लिए पड़ोसी राष्ट्र–राज्यों (म्यांमार, बांग्लादेश तथा भूटान) के साथ कूटनीतिक पहल करना बहुत ही समसामयिक एवं प्रासंगिक हो गया है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में भारत को सुरक्षा, व्यापार तथा बुनियादी ढांचे आदि पर आधारित तथा इसे बढ़ावा देने वाला संगठन बिम्सटेक (BIMSTEC) ("बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल" ÞBay of Bengal Initiative for Multi&Sectoral Technical and Economic Cooperation") जैसे बहुपक्षीय मंच का भी लाभ उठाना चाहिए, जो पूर्वोत्तर भारत तथा भारत के राष्ट्रीय हित के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।

वहीं दूसरी ओर, भविष्य में पड़ोसी राष्ट्र–राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के साथ–साथ आसियान ASEAN (दक्षिण दृ पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ Association of Southeast Asian Nations) राष्ट्र–राज्य के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार संबंधों, बुनियादी ढांचे में निवेश (विशेष प से भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली सड़कें तथा रेलवे जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देंगे), क्षेत्र के रणनीतिक स्थान का लाभ उठाने, एकीकृत सीमा प्रबंधन (ड्रोन, निगरानी प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीक) आदि के माध्यम से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

घ. आर्थिक विकास एवं सामाजिक स्थिरता: पूर्वोत्तर भारत में सड़क, रेल तथा हवाई परिवहन आदि का बुनियादी ढांचा अन्य भागों की तुलना में बेहद खराब है। जिसके कारण यहां रहने वाले मूल निवासियों, पर्यटकों तथा भारतीय सशस्त्र बलों आदि के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इन चुनौतियां के कारण आम जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती, पर्यटक आसानी से यात्रा नहीं कर पाते तथा सैन्य सामग्री शीघ्रता से नहीं पहुंच पातीं है। यद्यपि केंद्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने इस चुनौतियों को दूर करने के लिए अनेक विकास योजनाएं क्रियान्वित की हैं, फिर भी यह एक दीर्घकालिक समस्या बनी हुई है।

अतः पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद एवं अशांति को कम करने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत प्रासंगिक एवं समयानुकूल है। भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को भविष्य में इस क्षेत्र में औद्योगीकरण, कौशल विकास तथा कृषि सुधारों के साथ–साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME Micro] Small and Medium Enterprises) के विकास, पर्यटन निवेश को बढ़ाने तथा इस क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के प में बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना होगा, जिससे कि भविष्य में रोजगार सृजन हो सके तथा इन लोगों के जीवन स्तर में मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन तथा सुधार हो सके।

ङ. समावेशी शासन तथा आत्मनिर्भरता: जहां तक रणनीतिक अथवा सामरिक प्रतिक्रियाएँ तथा नीतिगत सिफारिश का प्रश्न है, उनमें स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता, समावेशी शासन के माध्यम से आत्मनिर्णय, शासन में स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना, विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देना तथा संवाद एवं विश्वास–निर्माण पहलों के माध्यम से जातीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना आदि शामिल होना चाहिए तथा एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ Special Economic Zone) को पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन एवं स्थानीय उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जो संभावित प से भविष्य के तनाव को कम कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करके समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

च. आपदा प्रबन्धन एवं पर्यावरण संरक्षण: पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ बाढ़, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आदि अक्सर आती रहती हैं। इससे न केवल सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, अपितु सैन्य गतिविधियों एवं आपातकालीन स्थितियों के लिए भी चुनौतियाँ पैदा होती हैं। इसलिए, भविष्य में इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर बाढ़ नियंत्रण तंत्र तथा आपदा–रोधी बुनियादी ढाँचा आदि।

पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में सतत विकास की प्रक्रिया ऐसी हो कि पूर्वोत्तर भारत अपने पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना सतत प से विकास कर सके तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत संसाधन प्रबंधन, वनीकरण एवं वन्य जीव संरक्षण आदि के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे पूर्वोत्तर भारत की पारिस्थितिक विरासत को समृद्ध, संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके तथा भविष्य में एक आदर्श प्रांत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके, जिसमें सामाजिक न्याय के आवरण में नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल का लाभ सभी नागरिकों को मिल सके।

निष्कर्ष– सीमांत भारत अथवा पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक, सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए नव–उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के काल में इस क्षेत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह भारत की सुरक्षा नीति, सीमा एवं क्षेत्रीय संतुलन आदि का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। परंतु यह क्षेत्र 21वीं सदी में भी उग्रवाद, सीमा विवाद, मानव तस्करी, घुसपैठ, सुरक्षा का अभाव, आतंकी घटनाएं, मादक पदार्थों की तस्करी, जातीय संघर्ष एवं बुनियादी ढांचे की कमी आदि अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत सरकार भी इन सभी मुद्दों को शक्ति के साथ सुलझाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। यदि भविष्य में मनसा–वाचा–कर्मणा के आधार पर सकारात्मक दिशा में मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन किए जाएं तो यह भारत का सामरिक दृष्टि से सुदृढ़, सशक्त एवं समृद्ध क्षेत्र बन सकता है।

इस प्रकार, 21वीं सदी में पूर्वोत्तर भारत के सामरिक महत्व एवं चुनौतियों को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह भारत के आर्थिक सशक्तीकरण, सुरक्षा तथा कूटनीतिक हितों का केंद्र बिंदु है। यह सर्वविदित है कि यह क्षेत्र आंतरिक उग्रवाद से लेकर सीमा विवाद एवं बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यावरणीय खतरों जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनका समाधान केवल बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा, कूटनीतिक जुड़ाव, आर्थिक सशक्तीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित प्रयासों से ही हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिरता एवं विकास न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है अपितु इसके सकारात्मक दूरगामी प्रभाव का उपयोग दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्षेत्रीय सहयोग एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत भविष्य में अपने समग्र रणनीतिक अथवा सामरिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण सेतु के प में पूर्वोत्तर भारत की क्षमता का सम्पूर्ण लाभ उठा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jant-Mar. 2025

1. दत्ता, रंजन कुमार, पूर्वोत्तर भारत, सामरिक एवं राजनीतिक परिपेक्ष्य प्रकाशक–बृज बुक्स, 2011, ISBN 978–8185275674 पृष्ठ संख्या 45–67
2. गोस्वामी, सत्येन्द्र, पूर्वोत्तर भारत, चुनौतियाँ और समाधान, प्रकाशक–राजकमल प्रकाशन, 2013, ISBN 978–8177493640 पृष्ठ संख्या 22–55.
3. गुप्ता, संजीव, भारत का पूर्वोत्तर सामरिक दृष्टिकोण, प्रकाशक– विनय प्रकाशन, 2015, ISBN 978–9381597554, पृष्ठ संख्या 78–101.
4. शर्मा, हिमांशु, पूर्वोत्तर भारत की सीमाएँ और सुरक्षा ,प्रकाशक– हिंदी साहित्य सेवा, 2017, ISBN 978–8190745498, पृष्ठ संख्या 120–145.
5. राहुल, कुमार, पूर्वोत्तर भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रकाशक– हिंदी बुक हाउस, 2018, ISBN 978–8192145012, पृष्ठ संख्या 33–57.
6. शिवलिंगम, नागेन्द्र, भारत के उत्तर–पूर्व ऐतिहासिक एवं सामरिक दृष्टिकोण, प्रकाशक–भारतीय प्रकाशन, 2009 ISBN 978–8175237581, पृष्ठ संख्या 50–75.
7. पाण्डे, दीपक पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह और उग्रवाद, प्रकाशक श्यामा प्रकाशन, 2012, ISBN 978–8171369022, पृष्ठ संख्या 99–123
8. मिश्र, सुशांत पूर्वोत्तर भारत की भू–राजनीति, प्रकाशक आस्था प्रकाशन, 2014, ISBN 978–9381490289, पृष्ठ संख्या 67–85
9. कुमार, रंजीत पूर्वोत्तर भारत में विकास और चुनौतियाँ, प्रकाशक जय प्रकाशन, 2016, ISBN 978–9382923791, पृष्ठ संख्या 58–80
10. अरोड़ा, समीर भारत का पूर्वोत्तर आर्थिक और सामरिक पहलू, प्रकाशक पुस्तकघर, 2013, ISBN 978–8182301270, पृष्ठ संख्या 123–145
11. सिंह, मनोज पूर्वोत्तर भारत सुरक्षा की दृष्टि से, प्रकाशक सस्ता साहित्य मंडल, 2015, ISBN 978–8177379112, पृष्ठ संख्या 102–125
12. मिश्र, कुमार भारत का पूर्वोत्तर सीमा सुरक्षा और उग्रवाद, प्रकाशक श्रीराम पब्लिकेशन, 2012 ISBN 978–9381919060, पृष्ठ संख्या 67–90.
13. 13.वर्मा, शैलेन्द्र पूर्वोत्तर भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, प्रकाशक इंद्र प्रकाशन, 2019, ISBN 978–8194023816,पृष्ठ संख्या 120–145
14. सिंह, प्रवीण पूर्वोत्तर भारत और भारत–चीन संबंध, प्रकाशक वी.एल.वी. प्रकाशन, 2016, ISBN 978–8193216444,पृष्ठ संख्या 130–152
15. गौतम, सुमित भारत का पूर्वोत्तर रणनीतिक महत्व, प्रकाशक उत्तर भारत पुस्तकालय, 2015, ISBN 978–9384174677,पृष्ठ संख्या 45–67
16. Bhaumik]Subir Troubled Periphery The Crisis of India*s North&East] Sage Publications] 2009 ISBN 978–8132102041.
17. Singh] S-P India*s North&East A Political Geography] Concept Publishing Company] 2005 ISBN 978&8180691711-
18. Gogoi] Ranjit North&East India A Sociological Perspective] M-D- Publications Pvt- Ltd-] 2003- ISBN 978&8175332357-
19. Majumdar] I- Strategic Importance of the North&East in India*s Foreign Policy- Kaveri Book Publishers] 2012- ISBN 978&8174791674-
20. Mishra] D-N- National Security Issues in the North&East] Academic Foundation] 2004- ISBN 978&8171884815-
21. Sharma] A- Ethnic Conflict and Insurgency in North&East India A Study of the Naga Insurgency] Daya Publishing House] 2005- ISBN 978&8170353199-
22. Goswami] S- Border States Challenges in India*s Northeast] Cambridge University Press] 2018- ISBN 978&1108405424-
23. Gupta] N-K- India*s Look East Policy and the Northeast Economic Implications] Abhijeet Prakashan] 2008- ISBN 978&8176482921-
24. https//hi-wikipedia-org] https//en-wikipedia-org] https//hi-wikipedia-org] https//en-wikipedia-org] https//hi-wikipedia-org & https//hi-wikipedia-org
25. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं (हिंदी एवं अंग्रेजी)।

*****